भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5263 का उत्तर

पुनर्विकास योजनाओं में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी की भूमिका

5263. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पांच वर्षों में तमिलनाडु में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है और उक्त परियोजना के लिए इन स्टेशनों का चयन करने हेतु किन मानदंडों का प्रयोग किया गया है;
(ख) इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;
(ग) इन पुनर्विकसित स्टेशनों पर अवसंरचना, यात्री सुविधाओं और पहुंच-सुविधा के संदर्भ में क्या सुधार किए गए हैं;
(घ) प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इस परियोजना के चरणों के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ङ) पुनर्विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) की क्या भूमिका है और विशिष्ट स्टेशनों के विकास के लिए यदि कोई निजी हितधारक शामिल किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;
(च) नियमित रेल-सेवाओं को बाधित किए बगैर स्टेशनों के पुनर्विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(छ) निर्माण के चरण के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेलवे स्टेशन का उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए, जिसमें प्लेटफार्मों का विस्तार भी शामिल है, कार्यों को

आवश्यकता, यात्री यातायात की संख्या और पारस्परिक आधार पर, धन की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है।

रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है, जिनमें से 77 स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य में विकास के लिए पहचाने गए स्टेशनों की सूची निम्नानुसार है:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
तमिलनाडु	77	अंबासमुद्रम, अंबत्तूर, अराक्कोणम जंक्शन, अरियलूर, आवडि, बोम्मिडी, चेंगलपट्टू जंक्शन, चेन्नई बीच, चेन्नई एग्मोर, चेन्नई पार्क, चिदंबरम, चिन्ना सेलम, कुरोम्पेट्टै, कोयम्बटूर जंक्शन, कोयम्बटूर नॉर्थ, कुन्नूर, धर्मपुरी, डॉ. एम.जी. रामचन्द्रन सेन्ट्रल, इरोड जंक्शन, गुडुवनचेरी, गुडुंडी, गुम्मिडीपूंडी, होसुर, जोलारपेट्टई जंक्शन, कन्याकुमारी, कराइक्कुडी, करूर जंक्शन, काटापाडी, कोविलपट्टी, कुलितुरई, कुंभकोणम, लालगुडी, मदुरै जंक्शन, माम्बलम, मनापरई, मन्नारगुडी, मयिलादुथुराई जंक्शन, मेट्टुपलयम, मोरप्पुर, नागरकोइल जंक्शन, नमक्कल, पलानी, परमक्कुडी, पेराम्बुर, पोदनूर जंक्शन, पोलाची, पोलुर, पुदुक्कोट्टई, राजापलायम, रामनाथपुरम, रामेश्वरम, सेलम, सामलपट्टी, शोलावंदन, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुथुर, सेंट थॉमस माउंट, ताम्बरम, तेनकासी, तंजावुर जंक्शन, तिरुवरुर जंक्शन, तिरुचेंदूर, तिरुनेलवेली जंक्शन, तिरुप्पादिरिप्पुलियूर, तिरुपत्तूर, तिरुपुर,

		तिरुशूलम, तिरुत्तानी, तिरुवल्लुर जंक्शन, तिरुवन्नामलाई, उदगमंडलम, वेल्लोर कैंट, विल्लुपुरम जंक्शन, विरुदुनगर, वृद्धाचलम जंक्शन, दिंडुक्कल, तूतीकोरिन

इन 77 स्टेशनों में से 71 स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। उपरोक्त कुछ स्टेशनों पर प्रगति निम्नानुसार है:

- मदुरै स्टेशन पर पूर्व की ओर बहु-स्तरीय दुपहिया वाहन पार्किंग और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का संरचना संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा पूर्व की ओर टर्मिनल भवन, दोनों ओर बहु-स्तरीय कार पार्किंग, एयर कॉनकोर्स, पार्सल पैदल पार पुल, सबवे आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर पार्सल भवन का संरचना संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा दोनों ओर बहु-स्तरीय कार पार्किंग, जीआई रोड की ओर टर्मिनल भवन आदि का कार्य शुरू हो गया है।
- तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम स्टेशन पर, उत्तर की ओर टर्मिनल भवन, विद्युत सब-स्टेशन और पार्सल कार्यालय के निर्माण का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और पूर्व की ओर टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य, आगमन प्रांगण, प्लेटफार्म सुधार आदि शुरू किया गया है।
- सामलपट्टी स्टेशन पर, नए मुख्य टर्मिनल भवन और मुख्य प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा दुपहिया वाहन पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफार्म को ऊंचा करने, परिसर की दीवार के निर्माण आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- कारैक्कुडि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेल्टर के सुधार का कार्य, बैठने की व्यवस्था, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, नए प्रांगण का निर्माण, प्रवेश और निकास द्वार, लिफ्टों और सवारी डिब्बा संकेतक बोर्ड संस्थापित करने का कार्य का पूरा कर लिया है। प्रतीक्षालय, आच्छादित मार्ग आदि का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है।
- अरियलूर और मन्नारगुडी स्टेशनों पर नए प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पोर्च के निर्माण, पहुंच मार्ग के साथ परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, कॉनकोर्स क्षेत्र,

बुकिंग काऊंटरों, प्लेटफार्म सतह, प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्म शेल्टरों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- विरुदुनगर स्टेशन पर नए प्रवेश द्वार, परिसर की दीवार का निर्माण कार्य, सेवा भवन का स्थानांतरण, प्लेटफार्म की सतह में सुधार, आच्छादित कवर्ड पार्किंग और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का प्रावधान आदि संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं तथा नए पैदल पार पुल का निर्माण, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पहुंच मार्ग आदि संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इस योजना में ऐसे प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, नि:शुल्क, वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है। इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन का सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टीरहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का विकास/उन्नयन आमतौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। तमिलनाडु राज्य दो जोनों यथा दक्षिण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन ज़ोनों के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,909 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि

शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है। बहरहाल, इस चरण में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। बहरहाल, सभी प्रयास यात्रियों को न्यूनतम असुविधा के साथ कामों को निष्पादित करने के लिए उचित सीमांकन और प्रभावित क्षेत्रों की बैरिकेडिंग, संकेतों और वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से किए जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों का पता लगाया है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य में रानी कमलापति स्टेशन पहले से ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया जा चुका है। वर्तमान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विकास के लिए 15 स्टेशनों की पहचान की गई है। परियोजना निर्माण एक जटिल और चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके लिए इष्टतमीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संबंध में विशिष्ट विवरण इस चरण पर नहीं दिए जा सकते।

*****